

[Dr. Golam Yazadani]

Ratua P. S. and Chanchal P. S. in the first week of June last, and due to widening of the breach, second phase of serious flood began in the middle of last month. This flood has unexpected, and serious damage to crops, houses and other properties has been done. The best relief will be to close the breach at Dhubal. Bihar Government has been trying to repair the breach, but complete repair has not been made yet. Due to partial repairs, flood water has been less than before, but still the flood has not yet receded completely. To ensure future crops, the breach should be completely repaired. As the civilian authority of Bihar Government has found it difficult to repair the breach upto now, it is desirable that the breach of the embankment may be repaired by military men on a war footing.

I draw the attention of the Hon. Minister of Irrigation of Centre to take up the matter and get the breach at Dhubal repaired effectively, immediately in the interest of the peasants and others of West Bengal and Bihar.

(iii) Need to reorganise Central Board of Film censors

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़ गढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के तहत सरकार का ध्यान सांस्कृतिक प्रदूषण की तरफ आकर्षित करना चाहूंगी।

विज्ञापनों, पोस्टरों, फिल्मों, अश्लील साहित्य द्वारा सांस्कृतिक प्रदूषण का जहर युवा पीढ़ी में फैल रहा है। इसके रोकथाम की मांग करूंगी।

वर्तमान में फिल्मों का माध्यम एक सशक्त माध्यम है, जिसका असर करोड़ों व्यक्तियों पर पड़ता है। पर अभी हम समाज में हिंसा फैलाने वाली संवस प्रधान फिल्मों

पर कोई नियंत्रण नहीं लगा पाये हैं। दक्षिण भारत की फिल्मों हिन्दी फिल्मों से भी अधिक बढ़ कर हैं।

11 41 hrs

[SHRI R. S. SPARROW in the Chair]

सैंसर बोर्ड पता नहीं कैसे उन्हें पास करता है। यह सत्य है कि अपराधियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही का अधिकार राज्य सरकारों पर है पर युवा पीढ़ी के लोगों में हिंसा और अपराधी प्रवृत्ति के बढ़ने हुए जहर को रोकना ही होगा। केन्द्रीय सरकार सख्त से सख्त कानून बना कर इस प्रकार सस्ते मनोरंजन के इस संशक्त माध्यम को विशाकन होने से बचाये। इस कठोर सत्य की ओर अब आँखें नहीं मूंदी जा सकती, इसलिए सरकार से मांग करूंगा कि

1. फिल्म सैंसर बोर्ड का पुनः निर्माण किया जाये।
2. कानूनों में भी संशोधन किया जाना अनिवार्य हो तो संशोधन किया जाये तथा युवा पीढ़ी की बढ़ती हुई अनुशासनहीनता, हिंसा, अपराध प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए।

(iv) Need to constitute a separate Pay Committee to look in to pay structure and service conditions of III Faculty

SHRI PRATAP BHANU SHARMA (Vidisha) : The five Indian institutes of Technology were established as Institutions of National importance by an Act of parliament and commensurate with objectives laid down in the very Act, these institutions have been contributing in the field of science and technology to help advance our nation on the path of industrial and scientific self-reliance.